



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 155]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 8, 2010/ज्येष्ठ 18, 1932

No. 155]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 8, 2010/JYAISTHA 18, 1932

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जून, 2010

विषय : चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित पैरा नाइट्रोनिलाइन (पीएनए) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जाँच की शुरुआत ।

फा. सं. 14/13/2010-डीजीएडी.—यतः घरेलू उत्पादकों, मै. अभिलाषा टेक्सकैम प्रा. लि., मुंबई और मै. अमरज्योत कैमिकल्स प्रा. लि., मुंबई ने 1995 में यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियम, 1995 (जिन्हें एतदपश्चात् पाटनरोधी नियम कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतदपश्चात् प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक याचिका दायर की है जिसमें चीन जनवादी गणराज्य (जिसे एतदपश्चात् संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित पैरा नाइट्रोनिलाइन (पीएनए) (जिसे एतदपश्चात् संबद्ध वस्तु कहा गया है) के कथित पाटन का आरोप लगाया गया है और संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने और ऐसी पाटित संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है ।

2. और यतः प्राधिकारी ने पाया है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग की क्षति तथा पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं और वे एतद्वारा किसी कथित पाटन की उपस्थिति, मात्रा एवं प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की राशि जिसे यदि लागू किया जाए तो वह घरेलू उद्योग की क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए उपरोक्त नियम के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन एवं परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई क्षति की जांच प्रारंभ करते हैं ।

क. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

3. वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद पैरा नाइट्रोनिलाइन (जिसे एतदपश्चात् "संबद्ध वस्तु" कहा गया है) है । यह एक अकार्बनिक रासायनिक यौगिक है । पैरा नाइट्रोनिलाइन को 4-नाइट्रोनिलाइन, 1-एमीनो-4-नाइट्रोबेंजीन या पी-नाइट्रोफेनाइलएमीन के नाम से भी जाना जाता है । सामान्य रूप से इस रसायन का प्रयोग रंजकों, एन्टीऑक्सीडेंट्स, भेषजों तथा गैसोलीन के सिथेसिस में मध्यवर्ती के रूप में, गम इन्हिबिटर्स, पोल्ट्री औषधियों में और कॉरोजन इन्हिबिटर के रूप में किया जाता है ।

सिंथेसिस में मध्यवर्ती के रूप में, गम इन्हिबिटर्स, पोल्ट्री औषधियों में और कॉरोजन इन्हिबिटर के रूप में किया जाता है।

4. इस उत्पाद का क्षेत्र सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 29 के अंतर्गत सीमाशुल्क उपशीर्ष सं. 2921.42.26 के तहत वर्गीकृत है। तथापि, यह सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी प्रकार से वर्तमान जांच के कार्यक्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

5. याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित वस्तुओं तथा चीन जन. गण. से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं में कोई ज्ञात अंतर नहीं है और वे वास्तविक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण इत्यादि जैसे मानदण्डों के संबंध में तुलनीय हैं तथा याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध देश से निर्यातित वस्तुओं में कोई विशेष अंतर नहीं है और दोनों तकनीकी तथा वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं को पाटनरोधी नियम के अनुसार संबद्ध देश से आयातित पाटित वस्तुओं के समान वस्तु के रूप में माना जा रहा है।

ख. घरेलू उद्योग तथा उसकी स्थिति

6. यह याचिका मै. अभिलाषा टेक्सकैम प्रा. लि. और मै. अमरज्योत कैमिकल्स प्रा. लि., मुंबई द्वारा दायर की गयी है और पनौली इंटरमीडिएट्स (इंडिया) प्रा. लि., प्रीमियर एग्रो कैम इंडस्ट्रीज प्रा. लि. और सौरभ ऑर्गेनिक्स प्रा. लि. द्वारा समर्थित है। रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार कुल घरेलू उत्पादन में समर्थक कंपनियों सहित याचिकाकर्ता के उत्पादन का हिस्सा प्रमुख है। अतः यह याचिका पाटनरोधी नियम के नियम 2(ख) की शर्तों को पूरा करती है।

7. प्राधिकारी ने उपर्युक्त की जांच के पश्चात यह निर्धारित किया है कि नियम 2(घ) के साथ पठित नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग हैं तथा उपर्युक्त नियम के नियम 5 के संदर्भ में याचिका दायर करने हेतु मानदण्डों को पूरा करते हैं।

ग. शामिल देश

8. वर्तमान जांच में शामिल देश चीन जनवादी गणराज्य है (जिसे चीन जन. गण. भी कहा गया है)।

घ. सामान्य मूल्य

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और इसलिए सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमों के अनुबंध-I के पैरा 7 और 8 के अनुसार किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने भारत को एक समुचित प्रतिनिधि देश के रूप में

माने जाने का प्रस्ताव किया है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा विनिर्मित मूल्य के आधार पर नहीं किया जा सकता है और अन्य देशों या भारत को तीसरे देशों से हुए आयातों की कीमतों का निर्धारण भी नहीं किया जा सकता क्योंकि ये आयात व्यवहार्यतः चीन जन. गण. से किए गए हैं। जाँच शुरूआत के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने प्रमुख कच्ची सामग्री, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन (पीएनसीबी) की निर्यात कीमतों का विश्लेषण किया है और चीन के सीमाशुल्क विभाग के अनुसार पीएनसीबी कीमतों के आधार पर सामान्य मूल्य पर विचार किया है जिसमें भारत में उत्पादन लागत के अनुसार अन्य सभी लागतों का विधिवत समायोजन किया गया है। इसमें बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय और तर्कसंगत लाभ मार्जिन शामिल हैं।

10. पाटनरोधी नियमावली के अनुसार पाटनरोधी जाँच की शुरूआत के औचित्य को सिद्ध करने के लिए सामान्य मूल्य के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है। तथापि, नियम के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा इस अधिसूचना में निर्धारित विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर चीन जन. गण. में सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु किसी समुचित तुलनीय देश के संबंध में सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

ड. निर्यात कीमत

11. याचिकाकर्ताओं ने जाँच अवधि में आईबीआईएस (अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सूचना प्रणाली) द्वारा प्रदत्त सौदे-वार आयात आंकड़ों के आधार पर भारित औसत आयात कीमत के रूप में संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत का निर्धारण किया है। कारखाना द्वार निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए निर्यात के देश में समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन संबंधी व्यय, बैंक प्रभार आदि के संबंध में समायोजन के दावे किए गए हैं।

12. पाटनरोधी नियम के अनुसार पाटनरोधी जाँच की शुरूआत के औचित्य को सिद्ध करने के लिए निर्यात कीमत के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं।

च. पाटन मार्जिन

13. कारखाना द्वार स्तर पर सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना की गई है जिसमें संबद्ध देश के संबंध में अत्यधिक पाटन मार्जिन प्रदर्शित होता है। जाँच के औचित्य को सिद्ध करने के लिए इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य मौजूद हैं कि संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत से बहुत अधिक है और संबद्ध देश से निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा संबद्ध वस्तुओं का पाटन किया जा रहा है।

छ. क्षति एवं कारणात्मक संबंध.

14. आवेदक ने वास्तविक क्षति से संबंधित विभिन्न मानदण्डों के बारे में सूचना उपलब्ध कराई है। सूचना के विश्लेषण से यह प्रदर्शित होता है कि जांच अवधि में संबद्ध देश से आयातों में समग्र अर्थों में और भारत में उत्पादन एवं खपत की तुलना में भी वृद्धि हुई है। बाजार हिस्से में हानि, कीमत कटौती, कीमत अवमूल्यन, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में अत्यधिक गिरावट, निवेश पर आय तथा नकद लाभ में अत्यधिक गिरावट आदि जैसे विभिन्न आर्थिक मानदण्डों से प्रथम दृष्टया यह संकेत मिलता है कि घरेलू उद्योग को चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति हुई है।

15. पाटनरोधी नियम के अनुसार पाटनरोधी जांच की शुरुआत के औचित्य को सिद्ध करने के लिए घरेलू उद्योग को क्षति और कारणात्मक संबंध से संबंधित पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं।

ज. जांच अवधि (पीओआई)

वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि (पीओआई) 1 जनवरी, 2009 से 31 दिसम्बर, 2009 है। तथापि क्षति जांच अवधि में वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 तथा जांच की अवधि शामिल होगी।

झ. सूचना प्रस्तुत करना

17. संबद्ध देश के उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकार, भारत में इस जांच से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए और निम्नलिखित पते पर अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है :-

निर्दिष्ट प्राधिकारी
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डीजीएडी)
कमरा नं. 240, उद्योग भवन
नई दिल्ली-110011

18. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से जांच से संगत निवेदन कर सकता है।

ट. समय-सीमा

19. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना लिखित में भेजी जाए जो प्राधिकारी के पास उपर्युक्त पते पर इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 40 दिन (चालीस दिन) के भीतर पहुँच जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी पाटनरोधी नियमों के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं। इस अधिसूचना के पैरा 10 में किए गए उल्लेख के अनुसार चीन जन. गण. हेतु प्रतिनिधि देश के चयन के संबंध में चीन जन. गण. में सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु समुचित तुलनीय देश का सुझाव देने के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिन के भीतर टिप्पणियाँ भेजने का अनुरोध किया जाता है।

ठ. अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

20. पाटनरोधी नियम के नियम 7 के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्राधिकारी को प्रस्तुत की गई किसी गोपनीय सूचना का अगोपनीय सारांश उसकी गोपनीयता बनाए रखने के कारणों सहित प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होता है। अगोपनीय रूपांतरण अथवा गोपनीय सूचना के अगोपनीय सारांश में पर्याप्त ब्यौरे होने चाहिए ताकि अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए सूचना की सार्थक समझ उपलब्ध करायी जा सके। यदि ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार की राय में ऐसी सूचना का सारांश नहीं बनाया जा सकता हो, तो उसके कारणों का विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

21. नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय रूपांतर वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

ढ. उपलब्ध तथ्यों का प्रयोग

22. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

पी. के. चौधरी, निर्दिष्ट प्राधिकारी

2193 GI/10-2

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)****INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th June, 2010

Subject : Initiation of anti dumping investigations concerning imports of Para nitroaniline (PNA) originating in or exported from China PR.

F. No. 14/13/2010-DGAD.—Whereas M/s. Abhilasha Texchem Pvt. Ltd., Mumbai and M/s. Amarjyot Chemicals Pvt Ltd., Mumbai, the domestic producers, have filed a Petition before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as AD Rules), alleging dumping of Paranitroaniline (hereinafter referred to as the subject goods), originating in or exported from the People's Republic of China (hereinafter referred to as the subject country) and have requested for initiation of anti-dumping investigations against the imports of the subject goods from the subject country and levy of anti-dumping duty on such dumped subject goods.

2. AND WHEREAS, the Authority finds that sufficient prima facie evidence of dumping of subject goods from the subject country, injury to the domestic industry and causal link between dumping and injury exist, the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping and consequent injury to the domestic industry in terms of the Rule 5 of the said Rules to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which, if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

A. Product under consideration and Like Article:

3. The product under consideration in the present investigation is Paranitroaniline (hereinafter referred as "subject goods"). It is an organic chemical compound. Paranitroaniline is also known as 4-nitroaniline, 1-amino-4-nitrobenzene, or p-nitrophenylamine. This chemical is commonly used as an intermediate in the synthesis of dyes, antioxidants, pharmaceuticals and gasoline, in gum inhibitors, poultry medicines, and as a corrosion inhibitor.

4. The scope of the product is classified under Chapter 29 (Organic Chemical) of the Customs Tariff Act under Customs Sub-heading No. 2921.42.26. However, the customs classification is indicative only and is not being considered in any way binding on the scope of the present investigation.

5. The petitioners have claimed that there is no known difference in petitioners' product and subject goods exported from the subject country and are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods and there is no significant difference in the subject goods produced by the petitioners and those exported from the subject country and both are technically and commercially substitutable. For the purpose of the present investigations, the goods produced by the domestic industry are being treated as like article to the subject goods imported from the subject country in accordance with the AD Rules.

B. Domestic Industry and Standing:

6. The petition has been filed by M/s. Abhilasha Texchem Pvt. Ltd. and M/s. Amarjyot Chemicals Pvt Ltd. and supported by Panoli Intermediates (India) Pvt. Ltd., Premier Orgochem Industries Pvt. Limited and Saurabh Organics Pvt Limited. As per the evidence available on record, production of the petitioners, along with the supporters commands a major share of the total domestic production. Petition thus satisfies the requirements of Rule 2(b) of Anti Dumping Rules.

7. The Authority, after examining the above, determines that the petitioners constitute domestic Industry within the meaning of the Rule 2(b) read with Rule 2(d) of the Anti Dumping Rules and the petitioners satisfy the criteria of standing in terms of Rule 5 of the Rules supra.

C. Countries involved:

8. The country involved in the present investigation is the People's Republic of China (also referred to as China PR.).

D. Normal Value:

9. The petitioners have claimed that China PR should be treated as non-market economy and therefore the Normal Value should be determined in accordance with Para 7 and 8 of Annexure-I of the AD Rules. The petitioners have proposed India to be considered as an appropriate surrogate country. The petitioners have claimed that the normal value cannot be determined on the basis of price or constructed value in a market economy third country and price from third countries to other countries or India could also not be determined as imports are practically from China PR. For the purpose of the initiation, the Authority has analyzed the export prices of the major raw material, Para Nitro Chloro benzene (PNCB) and considered normal value based on PNCB

2193 GI/10-3

prices as per China customs and all other cost as per cost of production in India duly adjusted to include selling, general & administrative expenses and reasonable profit margin.

10. There is sufficient evidence with regard to Normal Value to justify initiation of Anti dumping Investigations in terms of the AD Rules. However, in accordance with Para 7 to Annexure-I of the Rules, interested parties are hereby invited to suggest an appropriate analogue country for determination of Normal Value in China PR within the specific time limit laid down in this notification.

E. Export Price:

11. The petitioners have claimed export price of the subject goods from the subject country as the weighted average import price in the Period of Investigation, based on transaction wise import data provided by the IBIS (International Business Information System). Adjustments have been claimed on account of ocean freight, marine insurance, inland transportation, port expenses, bank charges etc. in the country of exports to arrive at ex-factory export price.

12. There is sufficient evidence with regard to Export Price to justify initiation of anti dumping investigations in terms of the AD Rules.

F. Dumping Margin:

13. Normal value and export price have been compared at ex-factory level, which shows significant dumping margin in respect of subject country. There is sufficient prima facie evidence to justify investigations that the normal value of the subject goods is significantly higher than the ex-factory export price and that the subject goods are being dumped by exporter(s)/producer(s) from the subject country.

G. Injury and Causal Link:

14. The applicant has furnished information on various parameters relating to material injury. Analysis of the information shows that imports from subject country have increased in the period of investigation in absolute term as also in relation to production and consumption in India. Various economic parameters like the loss in market share, Price undercutting, price suppression, significant decline in the profitability of the domestic industry, significant deterioration in return on investment and profitability, prima facie, indicate collectively that the domestic industry have suffered material injury on account of dumped imports of subject goods from China PR.

15. There is sufficient evidence with regard to injury to the domestic industry and the causal link, to justify initiation of anti-dumping investigations in terms of the AD Rules.

H. Period of Investigation (POI):

16. The Period of Investigation (POI) for the purpose of present investigation is 1st January, 2009 to 31st December, 2009. The injury investigation period will however, cover the periods 2006-07, 2007-08, 2008-09 and the Period of Investigation.

I. Submission of information:

17. The known producer(s)/exporter(s) of the subject country and their Government through their Embassy in India, the known importers and known users in India to be concerned and the domestic industry are being addressed separately to enable them to submit their relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the:

**The Designated Authority,
Ministry of Commerce & Industry,
Department of Commerce,
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties, (DGAD),
Room No. 240, Udyog Bhavan,
New Delhi-110011**

18. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

J. Time limit:

19. Any information relating to the present investigation and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the above mentioned address not later than forty (40) days from the date of publication of this notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Designated Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the AD Rules. With regard to selection of surrogate country for China PR as mentioned in para 10 of this notification, comments are hereby invited to suggest an appropriate analogue country for determination of Normal Value in China PR within 14 days from the date of notification.

K. Submission of Information on non-confidential basis:

20. In terms of Rule 7 of the AD Rules, the interested parties are required to submit non-confidential version of any confidential information provided to the Authority along with the reasons for claiming confidentiality. The non confidential version or non-confidential summary of the confidential information should be in sufficient detail to provide a meaningful understanding of the information to the other interested parties. If

in the opinion of the party providing such information, such information is not susceptible to summarization, a statement of reason thereof, is required to be provided.

L. Inspection of public file:

21. In terms of Rule 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

M. Use of facts available:

22. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

P. K. CHAUDHERY, Designated Authority